भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 134

12 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए नियत

फेम इंडिया योजना का चरण-II

***134. श्री रघु राम कृष्ण राजू:**
श्री सुमेधानन्द सरस्वती:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में (हाईब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया) योजना के चरण-II के दौरान प्राप्त उपलब्धियों और प्रगति का ब्यौरा क्या है और विभिन्न प्रकारों के आधार पर वर्गीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास आगामी वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाए जाने की दर में वृद्धि करने की कोई कार्यनीति अथवा योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग मंत्री

(डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय)

(क) से (ग) : विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

***

<u>विवरण</u>

"फेम इंडिया योजना का चरण-।।" के संबंध में लोकसभा में 12.12.2023 को उत्तर के लिए नियत श्री कानुमुरू रघु रामकृष्ण राजू, श्री सुमेधानंद सरस्वती के तारांकित प्रश्न संख्या 134 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): भारी उद्योग मंत्रालय ने कुल 10,000 करोड़ रूपए की बजटीय सहायता से 01 अप्रैल,2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण, चरण-।। (फेम इंडिया चरण-।।) स्कीम तैयार की है। इस स्कीम में, मुख्यतः सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण हेतु सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और इसमें 7,090 ई-बसों, 5 लाख तिपहिया वाहनों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों तथा 10 लाख ई–दुपहिया वाहनों के लिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। साथ ही, स्कीम के अंतर्गत चार्जिंग अवसंरचना के सृजन हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है। फेम-II इंडिया स्कीम के बारे में अधिक जानकारी वेबसाइट https://heavyindustries.gov.in/fame-ii पर देखी जा सकती है।

दिनांक 05.12.2023 की स्थिति के अनुसार, फेम इंडिया स्कीम के चरण-II के तहत 11,61,350 वाहनों की बिक्री पर इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं को 5248.00 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है।

आर्थिक प्रोत्साहन-प्राप्त इलेक्ट्रिक वाहनों का श्रेणीवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**वाहन का प्रकार**	**वाहन की कुल संख्या**
1.	दुपहिया	10,24,847
2.	तिपहिया	1,21,685
3.	चौपहिया	14,818
कुल		**11,61,350**

इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न शहरों/राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू)/राज्य सरकार की इकाईयों को अंतःशहरी प्रचालनों के लिए 6862 इलेक्ट्रिक बसों की स्वीकृति प्रदान की है। अद्यतन स्थिति अर्थात् अर्थात 29 नवंबर,2023 के अनुसार, इन 6862 ई-बसों में से 3487 ई-बसों की आपूर्ति एसटीयू को की जा चुकी है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने 7,432 इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तीन तेल विपणन कंपनियों को पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 800 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं।

(ख) और (ग): भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण की दर में वृद्धि और इलेक्ट्रिक वाहनों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित दो उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम शुरू की हैः

i. 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय वाली ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग विषयक उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम के अंतर्गत (इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके घटकों सहित) उन्नत मोटर वाहन प्रौद्योगिकी उत्पादों (एएटी) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। स्कीम के बारे में जानकारी https://heavyindustries.gov.in/pli-scheme-automobile-and-auto-component-industry पर देखी जा सकती है।

ii. सरकार ने 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण कार्यक्रम के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम को स्वीकृति दी है। यह स्कीम 50 गीगावाट घंटे के लिए देश में गीगा स्केल उन्नत रसायन सेल विनिर्माण केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। इन उन्नत रसायन सेल का उपयोग बैटरी में किया जाएगा जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन के व्यापक अंगीकरण को बढ़ावा देना है। स्कीम का ब्योरा https://heavyindustries.gov.in/pli-scheme-for-national-programme-on-advanced-chemistry-cell-acc-battery-storage पर है। इससे आगामी वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के घरेलू विनिर्माण में सहायता मिलेगी।

****